भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2495

सोमवार, 18 दिसम्बर /2023 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ से श्रमिकों का पलायन

2495. श्री चुन्नीलाल साहू:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकार के समन्वय से कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिकों/बेरोजगार युवाओं के पलायन से अवगत है;

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ से कितने श्रमिकों ने पलायन किया है; और

(च) सरकार द्वारा श्रमिकों/बेरोजगार युवाओं के पलायन को रोकने और जिस क्षेत्र में वे रहते हैं, उसके निकट रोजगार प्रदान करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के समन्वय से रोजगार के अवसर सृजित करने और ग्रामीण अवसंरचना में सुधार करने के लिए विभिन्न विकासात्मक स्कीमें कार्यान्वित कर रही है ताकि लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में कार्यान्वित की जा रही ऐसी कुछ योजनाएं नीचे दी गई हैं:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) में ऐसे ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के गारंटीयुक्त मजदूरी सहित रोजगार का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, देश में अधिसूचित सूखा प्रभावित क्षेत्रों या प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 100 दिनों के अलावा अतिरिक्त 50 दिनों का मजदूरी सहित रोजगार प्रदान किया जाता है।

जारी...2/-

ग्रामीण गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करके स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) लागू किया गया है।

ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्व-रोजगार के लिए कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। बैंक ऋण तक पहुंच के साथ यह प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर स्व-रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक होता है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) का उद्देश्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 'रर्बन क्लस्टर' नामक 300 ग्रामीण विकास समूहों को विकसित करना है, जिनमें विकास की अव्यक्त क्षमता है। इन समूहों की संकल्पना ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटने, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करने और अंतः प्रवास (रिवर्स माइग्रेशन) की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।

स्वरोजगार की सुविधा के लिए सरकार द्वारा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की गई थी। पीएमएमवाई के तहत सूक्ष्म/लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को 10 लाख रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं ताकि वे अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित या विस्तारित कर सकें।

सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से आरंभ होने वाले तथा 5 वर्षों की अवधि के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू की जा रही है, जिसमें 60 लाख नई नौकरियों के सृजन की क्षमता है।

पीएम गति-शक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों अर्थात् सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है, जो सभी के लिए बड़ी संख्या में नौकरी और उद्यमशीलता के अवसरों की ओर अग्रसर है।

पीएम विश्वकर्मा योजना में उन कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र (एंड-टू-एंड) सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जो कवर किए गए 18 ट्रेडों में उपकरणों का उपयोग करके अपने हाथों से काम करते हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से, असंगठित क्षेत्र के लाभार्थी अपने संचालन को बढ़ाने, अपने उपकरणों और व्यवसाय को आधुनिक / उन्नत करने और उद्यमियों के रूप में औपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने और राष्ट्र निर्माण के बड़े लक्ष्य की दिशा में योगदान करने में सक्षम होंगे। इस योजना का उद्देश्य ब्रांड संवर्धन और बाजार सहबद्धता के लिए एक मंच प्रदान करना है, ताकि उन्हें पात्र लाभार्थियों को विकास के नए अवसरों तक पहुंचाने में सहायता मिल सके।

इन पहलों के अलावा, सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, हाउसिंग फॉर ऑल आदि भी छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश में रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में उन्मुख हैं। इन सभी पहलों के गुणात्मक प्रभावों के माध्यम से दीर्घावधि में सामूहिक रूप से रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****